1987-88 and 1988-89; and

(b) if so, how much has been given to Kerala?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) The State sector Scheme of Environmental improvement of Urban-Slums aims at provision of basic amenities like drinking water, street lighting, community baths and latrines, paving of existing lanes and pathways etc. Funds for the Scheme are provided in the Annual Plan of the State Governments which are responsible for the formulation and implementation of these projects.

Bonded Labour in the country

2669. SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether there is any increase in the number of bonded labour in the country;

(b) whether any instructions have been issued to the State Government to launch a survey of bonded labour in their respective States; and

(c) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALVIYA): (a) Bonded labour identified during the last four years by the State Governments, is as follows:

Year	No. of bonded labour identified
1984-85	13,817
1985-86	17,561
1986-87	13,362
1987-88	16,385

(b) and (c) Under the provision of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976, the State Governments are to ensure that any system of forced labour does not survive in their States and wherever such practice is noticed, to take immediate steps to identify and release bonded labour. The implementation of the provisions of the Act are reviewed from time to time by the Central Government and State Governments are requested to enforce the provisions of the Act vigorously.

Milk processing plants in central sector

2670. SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) total number of milk processing plants in the central sector in the country; and

(b) how many such milk processing plants have been set up in Kerala?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

देश में बेरोजगार

2671. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय 35 वर्ष तक की आयु के कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं इनमें से कितने पूर्ण बेरोजगार हैं तथा कितने अर्ध बरोजगार हैं तथा शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों सहित शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) इस समय बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत प्रति-वर्ष कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तथा देश में प्रति-वर्ष बेरोजगारों

की संख्या में कितनी वृद्धि हो जाती है और सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ;

(ग) देश में वर्तमान बेरोजगारी की वृद्धि दर तथा जन-संख्या वृद्धि दर कितनी-कितनी है और क्या जनसंख्या में हो रही वृद्धि के अनुरूप लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं जाने की आशा है; और

(घ) इस समय राजस्थान में 35 वर्ष से कम आयु के कितने बेरोजगार व्यक्ति हैं और उन्हें उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा राजस्थान में प्रतिवर्ष बेरोजगारों की संख्या में कितनी वृद्धि हो जाती है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री **राधाकृष्ण मालवीय**) : (क) उपलब्ध सूचना 7वीं पंच-वर्षीय योजना दस्तावेज में दी गई सूचना के अनुसार है । उस स्रोत के अनुसार आयु वर्ग 5 + में सामान्य स्तर की बेरोजगारी मार्च, 1985 में 92 लाख थी । (22.4 लाख ऐसे व्यक्तियों सहित जिनके पास अनुपूरक कार्य था) जिसमें से 49.7 लाख ग्रामीण क्षेत्र में तथा 42.3 लाख शहरी क्षेत्रों में थे । उसी स्रोत के अनुसार, 1985 के आरम्भ में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 37 लाख थी ।

(ख) और (ग) रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न चालू विशेष योजनाओं के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) । 7वीं पंच-वर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार 1985-90 की अवधि के दौरान श्रम बल में 2.46% वार्षिक वृद्धि की तुलना में रोजगार 3.99% वार्षिक दर से बढ़ेगा । 7वीं योजना के अंत में बेरोजगारी योजना के शुरू से कम होने की संभावना है । सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए उठाए गए कदम 7वीं पंच-वर्षीय योजना दस्तावेज के खंड-I के अध्याय 3 तथा खण्ड II के अध्याय -5 में दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त, वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्रीय बजट प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ एक नए गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की व्यवस्था है जो ऐसे 120 चुने हुए जिलों को अतिरिक्त धन-राशि उपलब्ध कराएगा जो पिछड़े हुए हैं और जहां अत्यधिक बेरोजगारी है । इस नये कार्यक्रम से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार के पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे । इस योजना की निधियां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जिलों को उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त होंगी । बजट में इस नये कार्यक्रम के लिए 1989-90 में 500 करोड़ रु० की धन राशि की व्यवस्था है ।

(घ) उपलब्ध सूचना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (जनवरी-दिसम्बर, 1983) के 38वें दौर पर आधारित अनुमान है जिसके अनुसार राजस्थान में 5-29 आयु वर्ग में सामान्य स्तर के बेरोजगारों की संख्या 1.43 लाख थी । प्रश्न के भाग (ख) व (ग) के उत्तर में उल्लिखित कार्यक्रमों से भी राजस्थान में बेरोजगार व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है ।

विवरण

विशेष रोजगार कार्यालयों के अन्तर्गत की गई प्रगति

क्रमांक	कार्यक्रम	ईकाई	वर्ष	उपलब्धि
1.	आई आर डी पी	लाभभोगियों की संख्या (लाख)	1985-86	30.60
			1986-87	37.47
			1987-88	42.47
			1988-89 (दिसंबर, 88 तक)	23.62
2.	ट्राइसेम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (लाख)	1985-86	1.78
			1986-87	1.85
			1987-88	1.95
			1988-89 (दिसंबर, 1988 तक)	1.03
3.	शिक्षित बेरोजगार युवाओं में स्व-रोजगार को प्रोत्साहन देने संबंधी योजना।	लाभभोगियों की संख्या (लाख)	1985-86	2.2
			1986-87	2.17
			1987-88	1.20
			1988-89 (दिसंबर, 1988 तक)	0.23
4.	शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम (सेपप)	लाभभोगियों की संख्या (लाख)	1986-87	3.41*
			1987-88	3.82*
			1988-89 (फरवरी, 89 तक)	0.25
5.	एन. आर. ई. पी.	रोजगार के श्रम-दिवस (मिलियन)	1985-86	316.41
			1986-87	395.39
			1987-88	370.77
			1988-89 (जनवरी, 1989 तक)	255.43
6.	आर. एल. ई. जी. पी.	रोजगार के श्रम-दिवस (मिलियन)	1985-86	247.58
			1986-87	306.14
			1987-88	304.10
			1988-89 (जनवरी, 1989 तक)	179.72

*अनंतिम